STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir. The requirement of such a notification would arise only after zone units are approved and begin to effect imports;

(b) Yes, Sir.

(c) Issue of Customs and Central Excise Notifications for declaring Visakhapatnam Export Processing Zone as a bonded area has been taken up with the Department of Revenue and the same is expected to issue shortly.

इराक सरकार पर बकाया राशियां

3161. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की बड़ी-बड़ी राशियां इराक सरकार पर बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया की गत माहों में बैठक हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लगभग 2100 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि को वसूल करने में सरकार की मदद की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी हां ;

(घ) भारत सरकार तथा इराक के बीच आस्थगित भुगतान प्रबंधों के तहत इराक से तेल की खरीद के बदले तेल भुगतानों के कुछ अंश का समायोजन उन राशि के प्रति कर दिया गया था जिसका भुगतान उन परियोजना निर्यातकों को किया जाना था जिन्होंने इराक में परियोजनाएं निष्पादित की थीं । खाड़ी संकट आरंभ होने तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार रोक लगाए जाने से कच्चे तेल का आयात नहीं किया जा सका और इसलिए अगस्त, 1990 से आस्थगित भुगतान प्रबंध के तहत कोई भुगतान वसूल नहीं किये जा सके । सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के साथ जनवरी, 1991 में इस संभावना के बारे में मामला उठाया था कि इराक भारत को भारतीय निर्माण कंपनियों को दी जाने वाली बकाया राशि के बदले में तेल उपलब्ध कराए । तथापि, उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही । सरकार इराक पर से संयुक्त राष्ट्र व्यापार रोक उठाए जाने के बाद इराक भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रबंध की व्यवस्था कर सकती है ।

Associate Chambers of Commerce and Industry Statement on Export Target

3162. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported statements of Associate Chambers of Commerce and Industry stating that India can double its exports by 1995-96 if impediments are removed;

(b) if so, what is Government's reaction thereon; and

(c) what steps are proposed to be taken in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) A paper on 'Doubling Exports' in five Select Focus Product Groups by 1996-97' was circulated as a backgrounder for a Seminar on the subject organised by the Associated Chambers of Commerce and Industry of India in New Delhi on 14th August, 1993.

(b) and (c) Government is always responsive to suggestions that are conducive to growth in exports. Steps are taken whenever necessary to remove the problems brought up by trade and industry.

Export of Cigarettes

3163. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact U.S. cigarette manufacturers enhanced their exports to Japan from 3 billion pieces to 60 billion pieces between 1987 and 1992;

(b) whether it is also a fact that Indian premium brands of cigarettes are more price competitive as compared to their American counterparts;

(c) if so, what are our cigarette exports to Japan for the last three years;

(d) whether it is a fact that our domestic cigarette manufacturers are not entering Japan and other markets of advanced countries, since their parent